



सत्यमेव जयते



साप्ताहिक

खण्ड 38 अंक 32 पृष्ठ 64

नई दिल्ली 9 - 15 नवंबर 2013

₹ 8.00

अर्थव्यवस्था की स्थिति

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

शंखनाथ बंद्योपाध्याय

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में इच्छुक अर्थव्यवस्था में विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूंजी प्रवाह बढ़ाने के अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रोजगार के अवसर पैदा करने, नई प्रौद्योगिकी और जानकारी ग्रहण करने में सुविधा पहुंचाने और मानव पूंजी विकास में सक्षम बनाने तथा अधिक प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार माहौल पैदा करने में मदद पहुंचाता है। एफडीआई को आमतौर पर रचनात्मक और लाभप्रद समझा जाता है लेकिन प्राप्त करने वाली अर्थव्यवस्था पर इसके कुछ दुष्प्रभावों की भी आशंका होती है। बड़ी विदेशी कंपनियों की बाजार क्षमता से मेजबान अर्थव्यवस्था की लागत में बढ़ोतरी हो सकती है, जो छोटे घरेलू उत्पादकों पर भारी पड़ सकती है। इसके दुष्प्रभाव से अर्थव्यवस्था में कुछ वर्गों के लिए रोजगार के अवसरों में कमी आ सकती है और क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ने की आशंका रहती है। यह खतरा भी रहता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां घरेलू नीति प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने लगे। अर्द्ध विकसित अर्थव्यवस्थाओं में इसकी आशंका अधिक रहती है, जहां मेजबान देश की नीति प्राथमिकताओं पर इसका दुष्प्रभाव अवश्य पड़ता है। भारत में विदेशी निवेश के दो घटक हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में प्रचलित धारणा के अनुसार एफडीआई निवेशकर्ता के 'स्थायी हित' के लिए प्राप्तकर्ता देश के साथ एक दीर्घावधि संबंध है। किसी निवेश को एफडीआई का दर्जा देने के लिए यह जरूरी है कि विदेशी निवेशकर्ता को किसी निर्दिष्ट कंपनी में व्यापार या निवेश में 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हिस्सेदारी दी जाए।

यदि इक्रिटी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से कम होगी तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की श्रेणी में समझा जाएगा। अभी तक भारत में इस सिद्धांत का अनुपालन सख्ती के साथ नहीं किया गया है। किंतु, 2013-14 के बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री ने वायदा किया था कि दोनों प्रकार के विदेशी निवेश के बीच अंतर करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय मानदंड का अनुपालन किया जाएगा। इस मानदंड के अनुपालन की संभाव्यता के परीक्षण के लिए केंद्र सरकार ने एक पृथक समिति का गठन किया है जिसे एफडीआई और एफआईआई की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाने संबंधी समिति का नाम दिया गया है। अभी तक भारतीय संदर्भ में एफडीआई के अंतर्गत तीन घटक शामिल हैं:-(i) इक्रिटी, (ii) पुनर्निवेशित आय, और (iii) अन्य पूंजी। एफडीआई में इक्रिटी पूंजी ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट (यानी ताजा निवेश), अथवा ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट्स (अर्थात् अन्य कंपनी में निवेश/उसके मौजूदा शेयरों का अधिग्रहण या अन्य कंपनी के साथ विलय) शामिल हैं। किंतु, ब्राउन फील्ड निवेश आमतौर पर ग्रीन फील्ड निवेश एवं विलय एवं अधिग्रहण गतिविधियों का मिश्रित रूप होता है, और उसे अलग से दर्शाना कठिन हो सकता है। पुनर्निवेशित आय (अर्थात् वितरित न किया गया कार्पोरेट मुनाफा) किसी प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक के लाभ और शेयरधारकों को वितरित लाभांश के बीच एक तरह का अंतर है। अन्य पूंजी से अभिप्राय है एफडीआई निकायों का अंतर-कंपनी ऋण लेनदेन।

एफडीआई निवेश के माध्यम

वर्तमान नियामक फ्रेमवर्क के अनुसार, कोई भी भारतीय

कंपनी निम्नांकित माध्यमों से एफडीआई प्राप्त कर सकती है - (क) **ऑटोमेटिक रूट:** अर्थात् भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना ऐसे सभी क्षेत्रों/गतिविधियों में निवेश की स्वतः अनुमति होना, जिनका उल्लेख भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी समेकित एफडीआई नीति में किया जाता है; और (ख) **सरकारी मार्ग :** अर्थात् उन गतिविधियों में एफडीआई, जो स्वतः निवेश मार्ग के अंतर्गत नहीं आती हैं और जिनके लिए भारत सरकार से अनुमति लेनी होती है। ऐसे प्रस्तावों पर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें किसी भी माध्यम (स्वतः/सरकारी) से एफडीआई की अनुमति नहीं है, जैसे परमाणु ऊर्जा, लॉटरी व्यापार, जुआ और बाजी लगाना, निधि कंपनियों (अर्थात् म्यूचुअल लाभ वाली सोसायटी कंपनियों), और कुछ अन्य संवेदनशील क्षेत्र। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, एक नोडल विभाग है जो एफडीआई के बारे में भारत सरकार की नीति को अंतिम रूप देता है।

एफडीआई बहिर्प्रवाह के माध्यम

इसी प्रकार कोई भारतीय कंपनी भी किसी भी माध्यम से, अर्थात् स्वचालित या अनुमोदन के अंतर्गत विदेश में एफडीआई कर सकती है। स्वचालित मार्ग के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी को कुछ शर्तों और रियायतों के अधीन विदेशी कंपनियों में एफडीआई करने की अनुमति है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनेक भारतीय और विदेशी बैंकों को विदेश में ऐसी एफडीआई के लिए अधिकृत किया है।

भारत में एफडीआई

भारत में एफडीआई सक्षम संयंत्र विभिन्न राज्यों में फैले हैं लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में अपेक्षाकृत ऐसे संयंत्रों का अधिक संकेंद्रण है। ये ऐसे राज्य हैं जिनका औद्योगिक आधार (जैसे गुजरात) या तो बहुत सुदृढ़ है अथवा वे सॉफ्टवेयर के केंद्र (जैसे कर्नाटक) हैं। अन्य घटकों के अलावा इन राज्यों में बेहतर ढांचागत सुविधाओं (अर्थात् सड़कें और विद्युत) की वजह से भी एफडीआई संभव हुआ है। हालांकि यह पता चला है कि इन राज्यों में भी केवल कुछ शहरों में ही महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है जैसे अहमदाबाद, बंगलौर, चेन्नई, हैदराबाद, मुम्बई, पुणे आदि। इस तरह भारत में भौगोलिक वितरण की दृष्टि से देखें तो एफडीआई अपेक्षाकृत बड़े शहरों में ही अधिक हुआ है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, औषधियां एवं फार्मास्युटिकल उद्योग, आटोमोबाइल उद्योग और सेवा उद्योग आदि ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहे हैं। सेवा क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं का इस दृष्टि से वर्चस्व रहा है जबकि बैंकिंग और अन्य सेवा क्षेत्र का स्थान इसके बाद आता है। भारत जैसे देश में, जहां चालू खाता घाटा निरंतर बढ़ रहा है, एफडीआई पर निर्भर रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो अन्य देशों से संसाधन जुटाने का गैर-ऋण माध्यम है। लेकिन, प्राप्तकर्ता देशों में एफडीआई को “स्थायी और दीर्घावधि निवेश लक्ष्यों” की दृष्टि से देखा जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य तकनीकी ज्ञान, रोजगार के

(शेष पृष्ठ 64 पर)

रोजगार सारांश

सं.लो.से.आ.

- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित।
- अंतिम तिथि: 28.11.2013

आयुध निर्माणी

- आयुध निर्माणी अम्बरनाथ को 149 इलेक्ट्रिशियन, परीक्षक, मशीनिस्ट और मिलराइट की आवश्यकता
- अंतिम तिथि: प्रकाशन की तिथि से 21 दिन

सेल

- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राउरकेला को 231 ऑपरेटर-सह-तकनीशियन (प्रशिक्षु) और अटेंडेंट-सह-तकनीशियन (प्रशिक्षु) की आवश्यकता।
- अंतिम तिथि: 29.11.2013

भारतीय नौसेना

- भारतीय नौसेना द्वारा कार्यकारी शाखा (सामान्य सेवा/जल विज्ञान सवर्ग/सूचना प्रौद्योगिकी/नेवल आर्किटेक्चर) में अल्प सेवा कमीशन प्रदान करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से आवेदन-पत्र आमंत्रित।
- अंतिम तिथि: 29.11.2013

वेब विशेष

www.rojgarsamachar.gov.in पर वेब विशेष खण्ड में निम्नलिखित आलेख उपलब्ध है :

1. भारत का मंगल अभियान

कॅरिअर

सम्प्रेषण डिज़ाइन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर

कि सी उत्पाद का विज्ञापन, राजनीतिक अभियान अथवा पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता अभियान-किसी भी सम्प्रेषण रणनीति की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसका सम्प्रेषण डिज़ाइन कैसे तैयार किया गया है। चाहे कोई पोस्टर हो अथवा वीडियो, मुद्रित विज्ञापन, प्रदर्शनी स्थल, मोबाइल एप्लीकेशन अथवा साइन बोर्ड सम्प्रेषण के डिज़ाइन की विशिष्टता इसके भविष्य को तय करती है। वास्तव में ये सम्प्रेषण डिज़ाइन है क्या? इसके अलावा इस क्षेत्र के प्रति इतना ज्यादा आकर्षण क्यों है? आइए इसका पता लगाते हैं।

सम्प्रेषण डिज़ाइन का क्षेत्र डिज़ाइन के जरिए एक प्रभावी सम्प्रेषण के विकास से जुड़ा कार्य क्षेत्र है। यह चित्रों, ऑडियो और वीडियो से संबंधित मर्मस्पर्शी सामग्रियों का इस्तेमाल करने और इनके जरिए विचारों के प्रभावी सम्प्रेषण के बारे में होता है। ये सृजनात्मक और ग्राफिक कला, डिजिटल मार्केटिंग, लिबरल आर्ट, कमर्शियल आर्ट, विजुअल कम्यूनिकेशन और इसी तरह के अन्य क्षेत्रों से निकट से जुड़ा अंतर-विषयक क्षेत्र है।

सम्प्रेषण डिज़ाइनर्स सम्प्रेषण के उद्देश्य के लिए डिज़ाइन का अध्ययन और व्यवहार करते हैं। वे सम्प्रेषण रणनीतियों के सृजन के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ परंपरागत सम्प्रेषण दृष्टिकोणों को एक स्वरूप प्रदान करते हैं। वे मुद्रणकला, चित्रों, दृष्टांतों, एनीमेशन और वीडियो के सृजन के लिए भौतिक और डिजिटल माध्यमों का सतत प्रचालन करते हैं जो कि लक्षित व्यक्तियों की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के लिए काम करते हैं।

अनुप्रयोग

सम्प्रेषण डिज़ाइन ऐसी किसी भी पहल की सफलता का प्रमुख संचालक होता है जिसकी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच अपेक्षित होती है। ये प्रिंट, पब्लिशिंग, विज्ञापन, ई-शिक्षण, पैकेजिंग, विपणन और ब्रैंडिंग जैसी गतिविधियों की रीढ़ है। दरअसल सम्प्रेषण डिज़ाइन एक ऐसी व्यापक और शक्तिशाली गतिविधि है कि ये एक पूर्णतः नए क्षेत्र और विषयक्षेत्र के तौर पर उभरकर आया है। डिजिटल प्रौद्योगिकी में हुए विकास ने सम्प्रेषण डिज़ाइन की कला और विज्ञान में व्यापकता भर दी है। अब सोशल मीडिया इसे एक नई दिशा प्रदान कर रहा है।

सम्प्रेषण की ताकत के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण सम्प्रेषण डिज़ाइन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। चाहे कोई व्यावसायिक परियोजना हो या जनहित के मामलों से लेकर गैर लाभ वाली पहलें हों, सभी में सम्प्रेषण की मुख्य भूमिका होती है। दूसरी तरफ हाल के वर्षों में सृजनात्मक उद्योगों ने एक व्यापक वृद्धि दर्ज की है। इन कारणों से भारत में सम्प्रेषण डिज़ाइन उद्योग खूब पनप रहा है। सम्प्रेषण डिज़ाइनर्स के लिए अवसरों में जबर्दस्त वृद्धि हो रही है। साथ ही सम्प्रेषण डिज़ाइन अब युवाओं का एक लोकप्रिय कॅरिअर भी है।

अकादमिक

अकादमिक विकल्प के तौर पर सम्प्रेषण डिज़ाइन बैचलर्स और स्नातकोत्तर स्तरों पर उपलब्ध है। देश भर में बहुत से संस्थान सम्प्रेषण डिज़ाइन में विशिष्ट पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। इन पाठ्यक्रमों के जरिए कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सौंदर्यशास्त्र के बारे में ज्ञानवर्द्धन होता है, जो कि सम्प्रेषण डिज़ाइन से संबद्ध क्षेत्र हैं। इसमें ग्राफिक डिज़ाइन, एनिमेशन, ग्राफिक कला, ब्रैंड कम्यूनिकेशन और न्यू मीडिया जैसे विभिन्न विषय शामिल किये जाते हैं। इन पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु क्लासरूम अध्ययन, रियल-टाइम प्रोजेक्ट्स, उद्योग दौरे, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, पेपर सत्रों और मूल्यांकन परीक्षाओं का संतुलित मिश्रण है।

दृश्य संचार और ग्राफिक डिज़ाइन जैसे सम्प्रेषण डिज़ाइन से संबंधित पाठ्यक्रम में इसे संबंधित पाठ्यक्रमों के विषय के तौर पर शामिल किया जाता है। ऐसे भी कुछ संस्थान हैं जो सम्प्रेषण डिज़ाइन के एक या अधिक विशेषीकृत क्षेत्रों में पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे भी संस्थान हैं जो एनिमेशन फिल्म डिज़ाइन, प्रदर्शनी डिज़ाइन, चित्रांकन डिज़ाइन और सजीव इफेक्ट्स में पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। लेकिन एक समर्पित कार्यक्रम छात्रों को सम्प्रेषण डिज़ाइन के अधीन विभिन्न विषयों में निपुण करता है और उन्हें इस क्षेत्र में अपना कॅरिअर शुरू करने के लिए अपेक्षित ज्ञान और कौशल से सुसज्जित करता है। प्रस्तावित विशेषज्ञता, संस्थान की प्रतिष्ठा, कुल खर्च, अवसरंचना और संकाय आदि कुछेक क्षेत्र हैं, जिन पर छात्रों को कालेज का चयन करते समय विचार करना चाहिए।

(शेष पृष्ठ 64 पर)

सम्प्रेषण डिज़ाइन के ... (पृष्ठ 1 का शेष)

कौशल क्षेत्र
सम्प्रेषण डिज़ाइन एक सृजनात्मक, आकर्षक और चुनौतीपूर्ण कॅरिअर का क्षेत्र है. इस क्षेत्र में सफलता के लिए मज़बूत तकनीकी कौशल के अलावा, भावी व्यक्तियों को अपने सॉफ्ट कौशलों और गुणों में सुधार करना चाहिए. उदाहरण के लिये, जब प्रिंट मीडिया में काम करें तो अपने विचारों को एकल सांचे में ढालकर देखना चाहिए. अच्छे सजीव चित्रण विकसित करने के वास्ते भौतिक संसार का अवलोकन और इसकी गतिशीलता को समझना संदेश के सम्प्रेषण के लिए ज़रूरी होता है. फिल्म जैसे समय-आधारित माध्यमों में काम करने के लिए कहानी के प्रभावी वर्णन का कौशल होना चाहिए. भले ही कार्य का कोई भी क्षेत्र चुना गया हो, इसके लिए विचारों की मुखरता, गहन सोच-विचार, शोध अभिरुचि, समस्या-निदान कौशल और सृजनात्मकता आदि दूसरी पूर्वापेक्षाएं होती हैं.

रोज़गार की संभावनाएं
सम्प्रेषण डिज़ाइन उद्योग बहुत ही तेज़ी से विकसित हो रहा है. इस उद्योग में छात्रों के लिए अपना कॅरिअर शुरू करने, विभिन्न प्रकार के रोज़गार अवसरों को खोजने के व्यापक अवसर मौजूद रहते हैं. यह उनकी विभिन्न कार्य क्षेत्रों की पहचान, अनुभव प्राप्त करने और अपने कॅरिअर में उन्नति करने में भी मददगार होता है. इससे जुड़कर छात्र ग्राफ़िक डिज़ाइनर, एनिमेटर, प्रोग्रामर, एकाउण्ट्स एग्जिक्यूटिव, चित्रकार और कॉपीराइटर जैसे व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. विज्ञापन एजेंसियों, प्रकाशन गृहों, विपणन एजेंसियों, एनिमेशन कंपनियों, प्रोडक्शन गृहों, टेलीविजन चैनलों, मोबाइल एप्लीकेशन प्रदाताओं, पैकेजिंग कंपनियों, गेमिंग कंपनियों, वेब डिजाइनिंग कंपनियों, ई-शिक्षण कंपनियों और अन्य क्षेत्रों में अवसर मौजूद हैं.

देश में व्यावसायिक गतिविधियों की भरमार और हर क्षेत्र में हो रहे तीव्र विकास के साथ प्रतिभावान सम्प्रेषण डिज़ाइनर्स की व्यापक मांग है. इस क्षेत्र में न केवल लाभपूर्ण रोज़गार अवसर उपलब्ध हैं बल्कि यह सतत शिक्षण और व्यावसायिक रूप से संतोषप्रद कॅरिअर के लिए एक मंच भी उपलब्ध करवाता है.

कालेज	पाठ्यक्रम	पात्रता	प्रवेश	संपर्क
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	बैचलर ऑफ डिज़ाइन	10+2	प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन	www.iitg.ac.in
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, अहमदाबाद	फिल्म और वीडियो कम्प्यूनिकेशन एवं ग्राफिक डिजाइन में विशेषज्ञता के साथ डिज़ाइन में स्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम	10+2	प्रवेश परीक्ष में प्रदर्शन	www.nid.edu
जी इंस्टीट्यूट ऑफ़क्रिएटिव आर्ट, हैदराबाद	विजुअल कम्प्यूनिकेशन में बी.एससी	10+2	-	www.zica.org
एसआरएम यूनिवर्सिटी, काट्टनकुलाथुर	विजुअल कम्प्यूनिकेशन में बी.एससी	10+2	अर्हक परीक्षा में प्राप्त अंक	www.srmuniv.ac.in

प्रत्यक्ष विदेशी.. (पृष्ठ 1 का शेष)

अवसर आदि में बढ़ोतरी जैसे बृहत् सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पैदा करना है. एफडीआई अल्पावधि पोर्टफोलियो निवेश से

भिन्न है, जिसमें उतार-चढ़ाव होता रहता है. एफडीआई की मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही महत्वपूर्ण हैं. एफडीआई के एकाधिकार पूर्ण अधिकार की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता.

वाणिज्य संबंधी स्थाई संसदीय समिति की एक रिपोर्ट (फार्मास्युटिकल क्षेत्र में एफडीआई के बारे में 110वीं रिपोर्ट, जो 13 अगस्त, 2013 को राज्यसभा में रखी गई) के अनुसार घरेलू औषधि कंपनियों का बड़ी

विदेशी कंपनियों द्वारा अधिग्रहण किए जाने से उचित दरों पर महत्वपूर्ण औषधियां मिलना कठिन हो गया है.

भारत में खुदरा और बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने भी एक बहस को जन्म दिया है, जबकि इसके पक्ष में यह दलील दी जा रही है कि इससे बिचोलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी और अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे. साथ ही, उपभोक्ता उत्पादों में अधिक विविधता आएगी. खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विरोध में यह दलील दी जाती है कि इसका स्थानीय व्यापारियों (किराना दुकानदारों) और लघु उद्यमियों के हितों पर विपरीत असर पड़ेगा, क्योंकि वालमार्ट जैसी अपेक्षाकृत बड़ी कंपनियों का एकाधिकार कायम होने की आशंका है (अर्थात् घरेलू लघु उद्योग बड़ी विदेशी रिटेलर कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएंगे).

कुछ मामलों में प्राथमिकता क्षेत्रों (अर्थात् ढांचागत क्षेत्र) में एफडीआई आकर्षित करना कठिन होगा क्योंकि मुनाफे के अवसरों में कमी और दीर्घावधि की

गर्भावस्था अवधि को देखते हुए विदेशी निवेशकों द्वारा इन क्षेत्रों में रुचि प्रदर्शित करना कठिन है, बल्कि ऐसे निवेशक कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों (जैसे ई-गवर्नेंस और रिटेल आदि) में निवेश करना अधिक पसंद करेंगे.

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि भारत में एक व्यापक और निरंतर विकासशील बाजार है, प्रशिक्षित और अर्द्धकुशल श्रमिक बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिस्पर्धात्मक तकनीकी जानकारी (अनेक क्षेत्रों में) का आधार है. अतः देश को चालू खाता घाटे पर नियंत्रण करने के लिए मात्र एफडीआई का अंतर-प्रवाह बढ़ाने की बजाय एफडीआई की ऐसी नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए जिनसे बेहतर क्षेत्रीय विकास, रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी, नई प्रौद्योगिकी और जानकारी हासिल करने और मानव पूंजी विकास में मदद पहुंचाई जा सके.

(लेखक सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी (सीबीजीए) से सम्बद्ध हैं) ई-मेल sankhanath@cbgaindia.org)

न्यूज़ डाइजैस्ट

- चुनाव आयोग ने, चुनाव प्रचार अभियान में सामाजिक मीडिया के उपयोग के संबंध में व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं. अब सभी उम्मीदवारों को सामाजिक मीडिया पर, विज्ञापनों पर, व्यय सहित प्रचार अभियान पर, सभी व्यय के साथ विभिन्न सामाजिक मीडिया वेबसाइटों पर अपने आधिकारिक लेखा, राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व-प्रमाणन तथा सामाजिक मीडिया सहित इंटरनेट पर कंटेंट के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (आचरण संहिता) के अनुप्रयोग की घोषणा करना अनिवार्य है.
- भारतीय चुनाव आयोग ने नन ऑफ द अबव (इनमें से कोई नहीं) (एन.ओ.टी.ए.) बटन की डिज़ाइन को अनुमोदन दे दिया है, जो दिल्ली विधानसभा चुनावों में पहली बार प्रारंभ किया जा रहा है. अनुमोदित प्रतीक काली पृष्ठभूमि के साथ वृत्ताकार रूप में अंकित है, जिस पर अंग्रेजी के बड़े सफेद अक्षरों में एनओटीए लिखा है.
- उच्चतम न्यायालय ने केंद्र तथा राज्यों को कहा है कि जब तक संसद, सिविल सेवा बोर्ड (सी.एस.बी.) स्थापित करने में कोई उपयुक्त संविधान नहीं लाती, तब तक सिविल कर्मचारियों के सभी सेवा मामलों, विशेष रूप से स्थानांतरण, तैनाती, तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई पर राज्य सरकार का मार्गदर्शन करने एवं सलाह देने के लिए एक सिविल सेवा बोर्ड (सी.एस.बी.) की स्थापना करें. उसने यह भी कहा है कि सिविल कर्मचारियों की एक निर्धारित न्यूनतम तैनाती अवधि होनी चाहिए और वे मौखिक अनुदेशों या आदेशों के आधार पर कार्य नहीं कर सकते. इसलिए सिविल कर्मचारियों के कार्यों में जिम्मेदारी निर्धारित करने तथा जिम्मेवारी सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश या आदेश रिकॉर्ड करना अनिवार्य है.
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भुवनेश्वर तथा इम्फाल हवाई-अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई-हड्डों के रूप में अनुमोदन दे दिया है. इन हवाई अड्डों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों के रूप में घोषित करने से हवाई-यात्रियों को प्रतिस्पर्धी दर पर व्यापक सेवा विकल्प तथा उन्नत संपर्क सेवा मिलेगी, जिससे इन क्षेत्रों तथा देश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फार्मास्युटिकल्स परचेज पॉलिसी (पी.पी.पी.) का पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन कर दिया है. पी.पी.पी. के नवीकरण से फार्मा सी.पी.एस.ई (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों) की स्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग होगा और राष्ट्र की औषधि सेवा सुरक्षा सुनिश्चित होने के अतिरिक्त, जनता को कम मूल्य पर अच्छी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी.
- एयर मार्शल अरूप राहा अगले भारतीय वायुसेनाध्यक्ष होंगे. वे वर्तमान वायुसेनाध्यक्ष नेक ब्राउन के 31 दिसंबर, 2013 को सेवा-निवृत्ति के बाद कार्य ग्रहण करेंगे. एयर मार्शल अरूप राहा इस समय उप वायुसेनाध्यक्ष हैं.
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 5 नवंबर, 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, शार, श्री हरि कोटा से मंगल ग्रह पर भारत का पहला इंटरप्लेनेटरी यान भेजेगा. मंगल पर पहले भारतीय अभियान का मुख्य उद्देश्य एक अंतरग्रहीय अभियान के डिज़ाइन, नियोजन, प्रबंधन तथा परिचालन के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकियों का विकास करना है. (विवरण के लिए वेब-विशेष देखें).
- प्रख्यात हिंदी लेखक राजेन्द्र यादव का स्वर्णवास हो गया वे ‘नई कहानी’ आंदोलन के एक स्तंभ थे. लघु हिंदी कथाओं की शैली तथा विषय वस्तु में परिवर्तन इसी आंदोलन की देन है, ‘सारा आकाश’ इनका प्रसिद्ध उपन्यास है.

व्यावसायिक परिसर के विकास हेतु ऋण

- रु. 3.0 लाख तक का ऋण
- ब्याज दर 6% वार्षिक
- निजी अथवा पट्टे की जमीन हेतु
- हमारी वेबसाइट www.nhfdc.nic.in देखें



निःशक्तजनों का सशक्तिकरण

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनेन्स एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन

(निःशक्तता कार्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार)

रेड क्रॉस भवन, सेक्टर-12, फरीदाबाद-121007

दूरभाष : 0129-2287512, 0129-2287513, फैक्स : 0129-2284371

ई-मेल : nhfdc97@gmail.com, वेबसाइट : www.nhfdc.nic.in

रो.स. 32/8